मोदी सरकार के लेबर कोड के जमाने में मजदूर है बंधुआ दर बंधुआ

ग्राउंड जीरो से विवेक

फ़रीदाबाद बाईपास पर स्थित 'पृथ्वी कार फोम वाश' पर काम करने वाले 18 वर्षीय राजू और बब्बन को नहीं पता कि गाड़ी धुलाई के लिए पानी इस्तेमाल करने पर फ़रीदाबाद निगम कमिश्नर ने कितने कड़े नियम बनाये हुए हैं। राजू की मानें तो पुलिस कमिश्नर भी फिल्मों में ही होते हैं; उन जैसों के लिए तो असल में सिपाही ही होता है, और वह सिपाही पृथ्वी कार वाश के मालिकों से पैसे ले कर सारे कानून को कार की गन्दगी के साथ बहा देता है।

राजू ने बताया कि अलीगढ़ से दो साल पहले वो दिल्ली आया, कुछ दिन कबाड़े का काम करने के बाद एक दोस्त ने उसे इस कार वाशिंग सेंटर पर लगा दिया। यहाँ पैसे तो कबाड़े के काम से ज्यादा मिल जाते हैं पर गालियाँ भी उसी अनुपात में मिलती हैं। कितने पैसे मिलते हैं और कितनी देर के काम के लिए? इस पर राजू ने बताया कि 6000 रुपये महीना सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम के मिलते हैं। छुट्टी जैसी चीज उनके पैसे ही कटवाती है, इसलिए छुट्टी से कोई यारी नहीं।

बजबजाते गंदे कूड़े के ढेर में सुशोभित होता पृथ्वी कार वाश जिसके फ्लेक्स बोर्ड पर लिखा है कि वाईफाई की सुविधा मुफ्त होने के साथ-साथ पेटीएम् से भी भुगतान लिया जाता है। इन दो सेवाओं ने मोदी वाले डिजिटल भारत के सपने को सड़ते कूड़े और जानवरों के गोबर के बीच भी बिना किसी बीमारी के जीवित रखा हुआ है। पर इस तथाकथित स्वच्छ भारत में राजू जैसों की क्या हालत है इसको जानने के लिए 'मजदूर मोर्चा' की और से कई राजुओं से बात की गयी।

अनवर जो इसी बाईपास पर बने एक अन्य कार वाशिंग में काम करते हैं, ने बताया कि कृष्णपाल नामक एक व्यक्ति इस कार धुलाई सेंटर का मालिक है और लोकल होने के नाते उसने अनधिकृत रूप से ये कमरा बना लिया है। लगभग सभी कार वाश सेंटर ऐसे ही अनधिकृत रूप से चल रहे हैं। एक गाड़ी का 200-300 रुपया चार्ज किया जाता है। दिन भर में 10 गाड़ियाँ तो आ जाती हैं आराम से और अब जब बरसात का मौसम है तो उसमे तो रेला ही लगा है गाड़ियों की धुलाई का। पर मालिक तनख्वाह के नाम पर जो दिल करता है दे देता है। मजबूरी ये है कि कुछ महीने के पैसे रोक रखे हैं तो हम कही जा भी नहीं सकते अब इस काम को छोड़ कर। काम छोड़ा तो पैसे मर जाएंगे।

चारों ओर बेशुमार गन्दगी और सड़ते कचरे में लोटती पालतू भैंसें और सड़क पर सांप-सीढ़ी खेलते मनोहर लाल खट्टर के सांड, सड़ते बाईपास की खूबसूरती में चार चाँद लगा रहे हैं। पर इस खूबसूरती को अपनी जगह पर छोड़ खट्टर सरकार ने दारू के ठेके और बड़ी-बड़ी ऊंची आलिशान बिल्डिंगें बनाने का बीड़ा भी इसी के किनारे पर उठाया है। इन सबके बीच कार वाश जैसे असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के साथ क्या हो रहा है किसी को इसकी सुध नहीं।

गुरुग्राम सीमा पर, दिल्ली के आया नगर में बंबई का धारावी नए अंदाज में बन रहा है। टूटी और कीचड़ में सनी गलियों से होकर आप जी ब्लाक में राजा फार्म के नाम से मशहूर एक बड़ तीन एकड़ प्लाट में पाएंगे कि प्लाट के चारों तरफ 8 बाई 8 के 100 कमरे बने हुए हैं। हर कमरे में चार दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। कमरों में कोई अलमारी नहीं है और न ही कोई छज्जा, है तो बस चार इंच की दीवार और 5 फीट ऊँचा और 5 एमएम् का लोहे की चद्दर वाला दरवाजा। कमरों तक पहुचने के लिए मजदूर के शरीर का लचीला होना एक जरूरी शर्त है अन्यथा कीचड़ में गिर कर भी पहुच सकते हैं। इन्हीं सात फीट ऊँचे कमरों के बीचों बीच बना है 500 गज का आलिशान मकान जिसकी बालकनी में खड़े होकर प्लाट का मालिक संजय गुर्जर सभी मजदूरों पर नजर रखता है। इस तिलिस्मी वास्तुकला के पीछे छिपा है हिन्दुस्तानी अर्थव्यवस्था में मजदूर को पीसने का फन।

बारह साल से राजा फार्म में रह कर देहाड़ी मजदूर का काम करने वाले विकास यादव मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं। अपनी लम्बाई के बराबर का लगभग 16 ईंटों का चट्टा लगा कर एक बार में उसे दो माले चढ़ाने वाले विकास का बाहुबल संजय गुर्जर के सामने कहीं टिकता नहीं। इसका कारण संजय नहीं बल्कि हमारी पुलिस है।

42 वर्षीय मजदूर विकास ने बताया कि जिस कमरे में वो रहते हैं उसका किराया 2000 रुपये है। कोई अलमारी और छज्जा न होने का कारण यह है कि कोई सामान छुपाया न जा सके। फार्म के ऐन बाहर संजय ने अपने किराने की दूकान खोली हुई है। जो भी मज़दूर फार्म के भीतर कमरा किराये पर लेता है वो इसी दूकान से सामान लेने को बाध्य है। दुकान भी ऐसी सोच कर बनाई है कि कोई मजदूर मालिक कि आँख से बच कर न निकल सके। इतने के बाद भी यदि संजय को शक है कि कोई मजदूर किसी और दुकान से सामान ले आया है चोरी चुपके तो संजय किसी भी वक्त कमरे पर धावा बोल कर तलाशी ले लेता है और कोई अलमारी न होने के कारण कुछ छुपा पाना मुश्किल है।

16 साल के राजकुमार ठेके पर ईंट और बालू ढोने का काम करते हैं। राजकुमार ने बताया कि एक बार वो बाहर किसी अन्य किराने की दुकान से सरसों के तेल की बोतल ले आये। संजय ने उसी रात कमरे में घुस कर तलाशी ली और तेल मिलने पर पहले तो बोतल का सारा तेल गिरा दिया बाहर कीचड़ में और फिर बहुत मारा। किसी तरह कुछ बुजुर्ग मजदूरों ने उन्हें बचाया।

राजकुमार के साथ उसका दोस्त जावेद भी मोतिहारी से आया था। 16 साल का जावेद टाइल्स काटने का काम करता था। किसी घर में अच्छा काम करने के बदले उस घर के मालिक ने जावेद को अपना पुराना टीवी दे दिया था। एक दिन राजा फार्म का मालिक जब कमरे की तलाशी लेने लगा तो टीवी देख कर जावेद को दो तमाचे मारे और कहा कि बिजली का बिल तेरा बाप तेरी माँ से धंधा करा के देगा कुत्ते। जावेद ने अपशब्दों के विरोध में प्रतिक्रिया दी तो उसे मार-मार कर लगभग अधमरा सा करने के बाद जान से मारने के धमकी के साथ ही टीवी उठा ले गया मालिक। डर के मारे जावेद उसी रात बिहार भाग गया। इस तरह के वाकये आये दिन इस फार्म में होते हैं।

अपनी 14 साल के बहन को साथ रख मजदूरी करने वाले शुभम भी इस व्यापक शोषण का शिकार हैं पर मजबूरन इस फार्म में रहने को शापित भी हैं। एक दिन शुभम की बहन आरती पर फिकरा कसने के चलते शुभम का झगडा संजय के बेटे से हुआ। मार खाने के बाद शुभम ने पुलिस को फोन किया तो उल्टे पुलिस उसी को पीटने लगी। यहाँ तक की सिपाही ने ये भी कहा कि अपनी बहन को बोल कमरे में ही नहाया करे, बाहर नहाएगी तो अभी तो छेड़ा ही है बाद में रेप भी होगा।

वहां रह रहे दसियों मजदूरों से बात करने पर सबके पास कुछ न कुछ लुटने-पिटने की कहानियां थीं। इतने शोषण के बाद भी राजा फार्म में क्यों रहते हैं? 52 साल के शब्बीर आलम ने कहा कि जबसे आया नगर में प्लाट कटे तबसे यहाँ कमरे मिल रहे थे मजदूरों को।

शुरुआत में पूरे आया नगर में कमरे मिल जाते थे तो इस संजय का बाप ऐसा नहीं करता था, पर अब सब प्लाट बिक गए और ऐसी इक्का-दुक्का जगह बची है जहाँ मजदूर रह लेता है सस्ते में। ऊपर से सब जानते हैं कि यहाँ मजदूर रहते हैं तो ढूँढते हुए यहीं आते हैं। काम की गारंटी ने उन्हें संजय जैसों की गालियाँ और मार खाने पर विवश कर दिया है।

मजबूर मजदूरों की ये कहानियाँ सिर्फ राजा फार्म में समाप्त नहीं होतीं। बल्कि देश के हर कोने में राजा फार्म और संजय इनका खून चूस रहे हैं। सड़ती गन्दगी और कीचड़ में सने रास्तों से होकर जब मजदूर बाहर आता है तो उसे उसी संजय की दुकान से सामान लेना है। जिन्हें लगता है कि मजदूर निम्न कोटि का ही खाना खाता है तो उन्हें अपनी जानकारी में ये भी शामिल करना होगा कि वही निम्न कोटि का जो तेल बाहर 120 रुपए का मिलता है वो इस मजदूर को 130 में लेना प?ता है। आटे का जो बैग हमे 180 रुपये का मिलता है उसपर 180 लिखे होने के बावजूद भी वो आटा इनको 200 रुपये में लेना है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी हाल में कहा कि अच्छे दिन आ गए और अब देश बदल रहा है। किसके अच्छे दिन आये और किसका देश बदल रहा है ये तो वो ही जानें। पर देश की राजधानी के राजा फार्म और पड़ोसी हरियाणा के स्मार्ट शहर फरीदाबाद के बाईपास पर सड़ते कचरे में शोषित मजदूर तब भी पुलिस के पैसा खिलाऊ यार लूटेरे मालिकों से पिट रहा था और आज भी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है।

बंगाल से आने वाली लेबर को बंगलादेशी का तमगा दे कर रोज असुरक्षा का बोध कराया जा रहा है। जबकि एनसीआर में एक भी खाता-पीता घर ऐसा नहीं जिसकी सफाई-धुलाई ये गरीब न करते हों। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले मजदूर वोट देने बेशक बिहार जाते हैं पर उनका सबकुछ इसी राजा फार्म में सड़ रहा है। सुशासन बाबू के नाम से अपनी ब्रांडिंग कराने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने किसी रैली में ये नहीं कहा कि ये जो करोड़ों मजदूर बिहार से जाकर महानगरों में मर रहे हैं उनको मैं राजा फार्म वालों से कैसे बचाऊंगा। किसी केजरीवाल ने कभी ये नहीं कहा कि इस असंगठित क्षेत्र के गरीबों के हितों की रक्षा मैं कैसे करूँगा। पुलिस को समाज में शान्ति स्थापित करने की गारंटी बताने वाले एक भी योगी ने अपने क्षेत्र के मजदूरों के हितों को कानून का बलात्कार करने वाले पुलिस वालों से सुरक्षित करने की सिफारिश प्रधानमंत्री मोदी से नहीं की। और खुद प्रधानमंत्री जब 125 करोड़ देशवासी बोलते हैं तो क्या कभी जाना है कि इसमें शामिल 100 करोड़ मजदूरों की क्या दशा है?

फ्रेंड्स ऑटो के मज़दूरों को 2 माह से वेतन नहीं, मालिक सपरिवार यूरोप यात्रा पर

फ़रीदाबाद (म.मो.) एनआईटी के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट नम्बर 38 में स्थित यह कम्पनी विभिन्न वाहनों के लिये कई प्रकार के पुर्जे बना कर मुख्य वाहन निर्माता कम्पनियों को सप्लाई करती है। कम्पनी में करीब 300 श्रमिक काम करते हैं। इन में से करीब 250 ठेकेदारी में अथवा कैजुअल हैं। पक्के श्रमिकों को तो न्यूनतम वेतन मिल जाता है जबकि दूसरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं ईएसआई व भविष्य निधि के नाम पर काटी जाने वाली राशि का भी कोई ठिकाना नहीं। ईएसआई काटे जाने के बावजूद भी ईएसआई कार्ड नहीं दिया जाता।

इतना कुछ करने से भी जब कम्पनी मालिकान का पेट नहीं भरा तो श्रमिकों का वेतन भी रोक लिया। बीते दो माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर श्रमिक कम्पनी गेट पर धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दरअसल वाहन उद्योग में मंदी के चलते काम काफ़ी घट गया है, इसलिये मालिकान को अब उनसे काम कराने की कोई जल्दी नहीं है। वे मानते हैं कि दो-चार माह में अधिकांश श्रमिक रो-पीट कर चलते बनेंगे, जो रह जायेंगे तथा कुछ नये बेरोजगारों को पकड़ कर फ़िर काम चला लेंगे।

श्रमिक बताते हैं कि कम्पनी के मालिक सरदार अमरजीत सिंह चावला ने केनारा बैंक सहित कई बैंकों से 100 करोड़ के करीब कर्ज ले रखा है। इसके अलावा अनेक लोग़ों से भी भारी कर्जे ले रखे हैं। कर्ज के इन पैसों से अमरजीत परिवार ने प्लॉट नम्बर 58 में मेहर स्टील नाम से भी एक कम्पनी खोल रखी है। शहर में कई जगह इनके बड़े-बड़े प्लॉट तथा सेक्टर 15 में दो आलीशान कोठियां बना रखी हैं। घुमने के लिये महंगी लग्ज़री कारें रखी हैं। इस वक्त भी जब मज़दूरों द्वारा कमाया गया वेतन देने को तो उसके पास पैसा नहीं है, परन्तु सारा परिवार बीते दो सप्ताह से यूरोप के दौरे पर घूमने का आनंद उठा रहा है। ऐसे मेहनत के लुटेरों से निपटने के लिये मज़दूरों को संगठित हो कर अपने संघर्ष को आगे बढाते हुए फ़ैक्ट्री गेट तक ही सीमित न रह कर मालिकान के घरों तक का घेराव करना चाहिये। पूंजीपतियों के चंदे से चलने वाली सरकार व इसके बिके हुए अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस देश का कानून केवल पूंजीपतियों को ही संरक्षण प्रदान करता है।

विकास के नाम पर मोदी सरकार ने काट डाले 1,09,75,844 पेड़, हर साल काटे जा रहे 22 लाख पेड़

मोदी सरकार ने देश के विकास के नाम पर एक करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों की कटाई करवा डाली। सरकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बीते पांच सालों में 1 करोड़, 9लाख, 75 हजार, 844 पेड़ काट दिए गए। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक साल 22 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं।

दरअसल, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से लोकसभा में पूछा गया था कि देश में विकास कार्यों, निर्माण, जंगल में आग लगने और अन्य वजहों से पिछले पांच साल में कितने पेड़ों को काटा गया। इस पर लोकसभा में 26 जुलाई को अपने जवाब में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बताया कि 2014-15 में 23 लाख 34 हजार 319, 2015-16 में 16 लाख 96 हजार, 917, 2016-17 में 17 लाख 1 हजार 416, 2017-18 में 25 लाख 52 हजार 164 और 2018-19 में 26 लाख 91 हजार 28 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई।

मंत्रालय से यह भी पूछा गया था कि देश के कितने हिस्से में वन क्षेत्र या वृक्ष कवर क्षेत्र हैं। इस पर पर्यावरण

राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियों ने जवाब दिया कि देश में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाला संगठन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून वन क्षेत्रों का आकलन करता है, जिसके आंकड़े इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आइएसएफआर) में छापे जाते हैं।

आइएसएफआर-2017 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश का 8 लाख 2 हजार 88 वर्गमीटर वनक्षेत्र है यानी देश के कुल क्षेत्रफल का 24.39 फीसदी इलाका वन क्षेत्र है। सरकार की तरफ से कहा गया कि आइएसएफआर-15 की तुलना में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है।

पिछले चार वर्षों में और अधिक पौधे लगाने की योजना के बारे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि 87113.86 हेक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण शुरू करने और 56,319 घरों में वैकल्पिक ऊर्जा का उपकरण मुहैया कराने के लिए 12 राज्यों को जीआइएम के तहत अभी तक 237.07 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, पिछले चार वर्षों के दौरान (2015-16 से 2018-19 तक) 94828 हेक्टेयर नए क्षेत्र का सुधार करने के लिए राज्यों को एनएपी के तहत 328.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06